पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाः एक परिचय

*रविन्द्र कुमार मीना

सार

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' (ERCP) राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। जिसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अधिशेष जल का उपयोग राज्य के उन दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है ; जहाँ पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव है। ERCP में राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से बाढ़ के समय आने वाले अतिरिक्त पानी को संग्रहित करके, बाढ़ से होने वाली फसल की हानि को रोका जा सकेगा। राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूरी होने की उम्मीद जगी है। फ़िलहाल मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच दिल्ली में हुई बैठक में नए एमओयू पर सहमति बनी है। इस शोध आलेख को प्रकाशित करने का उदेश्य उक्त परियोजना को जनमानस के लिए नीति निर्धारण करने वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियो तक पहुँचाना है, जिससे यह जीवनदायनी परियोजना त्वरित गति से लागु हो सके।

शब्दकोश- नहर-परियोजना,सिंचाई,सरकार,जीवन-रेखा,जन-जीवन,जीवनदायनी इत्यादि।

:

1. परिचय

यह एक बहुउदेशीय परियोजना है । जिसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियों के अतिरिक्त पानी को काम लाना है। जिससे इस अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल सिचांई तथा पेयजल के रूप में किया जा सके। इस परियोजना का लाभ पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगा। जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, धौलपुर तथा अलवर है ।

सर्वप्रथम 2017-18 के बजट में इस परियोजना की घोषणा हुई थी। इस दौरान सरकार ने कहा था कि ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की दीर्घकालिक सिंचाई और पीने की पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी| 2017-18 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय महत्व वाली परियोजना के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस परियोजना को 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा भी इसे स्वीकृति मिली । तभी से सरकारों की लगातार मांग बनी हुई है । ERCP को वर्ष 2051 तक पूरा किये जाने की योजना है, जिसमें दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के पानी तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।

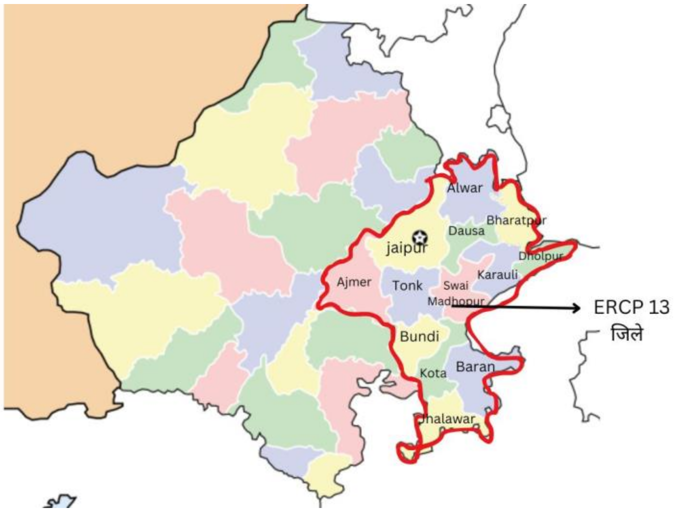

चित्र 1 **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरपीसी)मे शामिल राजस्थान के 13 ज़िले**

2. **पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की आवश्यकता**

राज्य जल संसाधन विभाग राजस्थान के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 342.52 लाख हेक्टेयर है, जो पूरे देश का 10.4 प्रतिशत है। वहीं भारत के सतही जल का केवल 1.16 प्रतिशत और भूजल का 1.72 प्रतिशत यहां है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरपीसी) का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान की जल प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसके माध्यम से पूर्वी राजस्थान में स्थित चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कि कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित नदियों को जोड़ना है साथ ही इन नदियों में बारिश के मौसम के दौरान इकट्ठे होने

वाले पानी की उपयोगिता बढ़ाना भी है, ताकि राज्य के दक्षिण-पूर्वी जिले में पीने और सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग कर सके। ऐसे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के पानी की समस्या को दूर कर पाने में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकती है।इसमें राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है | इस परियोजना से नवनेरा बैराज, मेज एनीकट तथा गलवा बांध में पंपिंग एवं विद्धूत स्टेशन स्थापित किए जाएंगे | इस परियोजना से बाढ़ के समय आने वाले अतिरिक्त पानी को संग्रहित करके, बाढ़ से होने वाली फसल की हानि को रोका जा सकेगा तथा इस अतिरिक्त पानी से विभिन्न प्रकार के कार्य पूरे किए जाएंगे।(4)

3 . **पूर्वी राजस्थान को इस परियोजना से होने बाले लाभ**

1. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से राजस्थान में निरंतर गिर रहे भूजल स्तर को रोकने में मदद मिलेगी।
2. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत बीसलपुर बांध की ऊंचाई को आधा मीटर तक बढ़ाया जाएगा जिससे बीसलपुर बाँध की जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी।
3. यह योजना राजस्थान के परिवहन तंत्र में मददगार होगी इस के द्वारा लगभग 200 किलोमीटर लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
4. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canal Project- ERCP) के तहत प्रथम चरण मे वर्ष 2040 तक राजस्थान की घनी आबादी वाले तीन जिले अजमेर, जयपुर एवं टोंक जिले की पेयजल की जरूरतों पूरा करते हुए अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी।
5. इस परियोजना के माध्यम से बाढ़ तथा नदियों के व्यर्थ बह रहे पानी को रोका जाएगा। इसमें राजस्थान राज्य की समस्त नदियों में बह रहे फालतू पानी को बांधों के जरिए रोककर राज्य में उपयोग में लिया जाएगा।
6. दो लाख हेक्टर नये भू-क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
7. राज्य के ग्रामीण इलाकों में भूजल तालिका (Ground Water Table) में सुधार होगा।
8. यह लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करेगी।
9. यह परियोजना विशेष रूप से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (Delhi Mumbai Industrial Corridor-DMIC) पर ज़ोर देते हुए इस बात की परिकल्पना करती है कि इससे सतत पोषणनीय जल स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा जो क्षेत्र में उद्योगों को विकसित करने में मदद करेंगे।(3)

10 .करौली के संदर्भ में हम देखते तो पाते है की पांचना बांध से निकलने बाली गंभीर नदी, जो राष्टीय अभ्यारण्य घना पक्षी विहार भरतपुर से होते हुए यमुना में मिलती है। विगत सालों में इस नदी का अपवाह क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। क्योकि इसमें पानी का बहाव नियमित नही रहा है उसकी वजह है अपर्याप्त वर्षा| इसके दुष्परिणाम की चर्चा करे तो हम पाते है कि सन 1980 में नदी के आस पास बाले गांवों में भूजल स्तर 15 फीट पर था, पर विगत वर्षो में क्षेत्र में नदी के अनियमित अपवाह की वजह से अब वर्त्तमान 2024 में यह भूजल इस्तर 150 फीट नीचे चला गया है। इस स्तर पर उपलब्ध भूजल सिचाई एवं पेयजल हेतु अपर्याप्त है। इसकी वजह से स्थानीय लोग गहरे नलकूप खोद रहे है जिनमे सभी को पानी नहीं मिलता है। इस स्थिति मे उस परिवार को

बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुचती है। जिसकी पूर्ति उस किसान परिवार से हों नहीं पाती है। फलस्वरूप वह कर्ज मे डूबता जा रहा है। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत आबादी इसी समस्या से पीड़ित है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इन लोगों के जीवनदायनी सिद्ध होगी। तथा राष्ट्रीय घना पक्षी विहार अभ्यारण्य भरतपुर को भी पानी उपलब्ध हों पायेगा।

4 .राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राजस्थान सरकार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाह रही है क्योकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने का मुख्य लाभ यह होगा कि परियोजना को पूर्ण करने हेतु 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और 10% राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी साथ ही इस बड़ी परियोजना की बेहतर तरीके से मॉनीटरिंग होगी ओर बेहतर तकनीक के साथ कार्य को गति मिलेगी

पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी बहती है. इस नदी में हर साल 20 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी यमुना-गंगा के जरिए बंगाल की खाड़ी में बेकार बह जाता है. यही पानी हर साल बाढ़ का कारण भी बनता है. इन बेकार बहकर जाने वाले पानी के उपयोग के लिए ईआरसीपी योजना बनाई गई है.

इस परियोजना के तहत मानसून के दिनों में कुल 3510 एमसीएम पानी जिसमें 1723.5 पेयजल, 1500.4 एमसीएम सिंचाई और 286.4 एमसीएम पानी को उद्योगों के लिए चंबल बेसिन से राजस्थान की दूसरी नदियों और बांधों में शिफ्ट करना है.

इसके लिए पार्वती, कालीसिंध, मेज नदी के बरसाती अधिशेष पानी को बनास, मोरेल, बाणगंगा और गंभीर नदी तक लाया जाना है. कुल मिलाकर ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान की 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है. परियोजना के पूरे होने से मानसून में बेकार बहकर जाने वाले बाढ़ के पानी का उपयोग होगा. इसी से 13 जिलों को सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी मिल सकेगा.

5 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की चुनौतियाँ

किसी परियोजना को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान करने हेतु सबसे पहले केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है ,इसके बाद जल शक्ति मंत्रालय की सिचाई, बाढ़ नियंत्रण, एवं बहुद्देश्यीय सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर राज्य सरकार द्वारा निवेश मंजूरी प्राप्त करनी होती है । इस परियोजना के अटकने के पीछे तीन मुद्दे हैं। पहला मामला है नदियों के पानी के उपयोग की डिपेंडेबिलिटी। राष्ट्रीय परियोजना के लिए इसका प्रतिशत 75 होना चाहिए, जबकि ईआरसीपी के मामले में यह 50 फीसदी है। दूसरा मामला मध्यप्रदेश से एनओसी का है। मध्यप्रदेश से आने वाली नदियों के पानी के उपयोग के लिए एनओसी अभी तक नहीं मिल सकी है। मध्यप्रदेश को यह भी लग रहा है कि राजस्थान उनके हिस्से का पानी ले लेगा। तीसरा मामला इंटरस्टेट विवाद पर केंद्र के दखल का है। ऐसे इंटरस्टेट विवादों को केंद्र, साथ बैठकर हल कराता है। लेकिन ईआरसपी मामले में कई बैठकों के बाद भी पेच 50 फीसदी डिपेंडेबिलिटी के चलते डीपीआर पर अटका हुआ है। इन सब मुददों पर आपसी सहमति के बाद अंतिम रूप से उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (HPSC) द्वारा अनुशंसा किये जाने पर केंद्र द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है।

2017-18 में इस परियोजना की अनुमानित लागत 37200 करोड़ थी जो देरी होने के कारण वर्तमानमे 70000 करोड़ हों गई है । इसकी डीपीआर केन्द्र सरकार के उपक्रम वेप्फॉस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार 37200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना को वर्ष 2016-2017 में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार ने बनाया था। राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिये बजट सत्र 2023-24 में 9600 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया है।

6 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कार्यप्रणाली

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस परियोजना के तहत होने वाले समस्त प्रकार के कार्यों के लिए तक़रीबन 13000 करोड़ रुपए के व्यय करने की घोषणा की थी। राजस्थान सरकार द्वारा ERCP परियोजना को केंद्र से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की गयी थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा स्वयं के स्तर पर ही इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया

अब वर्त्तमान में ईआरसीपी की मांग को लेकर पूर्वी राजस्थान में कई मोर्चे अस्तित्व में आ गए हैं. वहीं, कई स्थानीय नेता, सामाजिक और कृषि संगठन एकजुट होने लगे हैं. इन्हीं में से एक है ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा. मोर्चे के अध्यक्ष जवान सिंह ने बीते दिनों ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं अभियान का आगाज़ किया है.

वे कहते हैं, "ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी| क्योंकि आज भी धौलपुर, करौली जिसे जिले देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं. खेतों को पानी मिलेगा तो लोगों का आर्थिक विकास भी होगा और यह क्षेत्र मुख्यधारा में आ सकेगा."

स्थानीय लोगों द्वारा ईआरसीपी पर बनाये गये नारे -

'' बंजर धरती करे पुकार चम्बल पानी लाओ सरकार ''

'' जनता को जगाना है ....चम्बल का पानी लाना है ''

'' 36 कोम का नारा है ERCP हक़ हमारा है ''

'' पाणी चम्बल ल्यावनो , जेई भगबान छ म्हारो ''

राजस्थान सरकार का कहना है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर मध्यप्रदेश-राजस्थान अंतर राज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड की साल 2005 में बैठक में हुए निर्णयों के अनुसार बनी है. इस निर्णय के अनुसार 'राज्य किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी और दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10 प्रतिशत प्रयोग इस शर्त के साथ कर सकते हैं- यदि परियोजना में आने वाले बांध और बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है.

7 निष्कर्ष

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो की अभी हाल चर्चा मे है। इसके बनाने के उदेश्यों की बात करे तो हम देखते है की राज्य की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्मी राजस्थान मे चल रही है। क्योंकि जहाँ पानी की कमी है वहां रेगिस्तान का प्रसार माना गया था। पूर्वी राजस्थान को प्रचुर पानी का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में पूर्वी

राजस्थान में भू जल स्तर में कमी देखी जा रही है। अब यहाँ पानी के सोर्स धीरे-धीरे खत्म होने लगे। भूजल स्तर में पिछले दशकों से लगातार गिरावट हुई है फलस्वरूप वर्तमान में पूर्वी राजस्थान मे पचिमी राजस्थान के जैसे हालात होने के आभास दिखाई देने लगे है। इस परिस्थिति में यह परियोजना यहाँ पीने के पानी व सिंचाई के पानी की उपलब्धता करवायेगी। अतः यह परियोजना यहाँ के लोगों के जनमानस एवं उनकी भावना के रूप बनाई गई है।

***सहायक आचार्य–भूगोल**
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

सन्दर्भ

1. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/jaipur/pm-modi-promise-not-fulfill-why-ercp-project-ashok-gehlot-want-it-larger/articleshow/81572127.cms
2. https://sujasbulletin.com/purvi-rajasthan-nahar-priyojana-ercp-2023/
3. https://rajasthancurrentaffairs.in/ercp-rajasthan/
4. https://youthdestination.in/east-rajasthan-canal-project-hindi/
5. mentioned-by-pm-modi-and-ashok-gehlot
6. https://www.kisantak.in/news/story/rajasthan-budget-2023–what-is-ercp-irrigation-project-mentioned-by-pm-modi-and-ashok-gehlot-509692–2023–02–09
7. https://www.youtube.com/watch?v=lzLbOPc6lec